northern rivers with the southern rivers—the Sindh, the Jhelum and the Chenab, with those rivers.

MR. CHAIRMAN: The question is out of scope. I have allowed it only because the Minister is speaking for the first time.

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, during the last 12 years, amounts have been provided in the Budget for developing inland waterways, one of which is the waterways from Quilon or Kollam to Kodumgallore, there are certain others also. But even though amounts have been provided in the Budget, the works are not being taken up seriously; it is not progressing.

**Coverage of FM Radio**

*371. SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the total number of FM Radio Stations in the country;

(b) the percentage of population covered by these Stations;

(c) how many new FM Radio Stations are proposed to be started during the Tenth Plan, year-wise; and

(d) by when Government hope to achieve full coverage of FM Broadcast?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House:

***Statement***

(a) 133 FM Radio Stations of All India Radio are presently functioning in the country. AIR is also operating 6 FM Stations of Gyan Vani Channel of Indira Gandhi National Open University (IGNOU). In addition, 10 private FM channels are also operational.

(b) 31.34% of population is covered by AIR FM Radio broadcast.

(c) 95 new FM stations (including replacement of 12 existing MW transmitters) and upgradation of 18 existing FM Stations of AIR are envisaged during the Tenth Five Year Plan.

(d) Full coverage through FM broadcast, will depend on the availability of resources and it is not possible to give a definite time-frame in this regard. However, after the implementation of Tenth Five Year Plan Projects, FM coverage is expected to be available to about 50% population of the country.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, this question relates to increasing the coverage by FM broadcasting system in the country. The Ministry has replied that A.I.R. is operating six FM stations of Gyan Vani Channel of the Indira Gandhi National Open University. My specific question is: Would you permit the open universities which are run by the various State Governments like the Yashwantrao Chavan Open University in Maharashtra, to broadcast their programmes? Is there any application received from them to run FM channels on your Station, by using your equipment? Also, will you permit the State Governments to have their own FM channels? In the State agricultural universities are there, open universities are there. What is your policy for installing/running FM channels?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, मुझे आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि एक नयी नीति हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं जिसके तहत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्टेट्स में चलने वाली यूनिवर्सिटीज IIM, IITs, यहां तक कि रेजिडेंशियल स्कूल्स भी छोटे FM फ्रीक्वेंसी बैंड पर अपने रेडियो स्टेशन लगा सकते हैं। इसके लिए अभी हम कैबिनेट में जा रहे हैं और यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर हम कैबिनेट में जा रहे हैं। अगर इसको कैबिनेट से अनुमोदन मिल जाता है तो निश्चित तौर पर माननीय सांसद ने जो चाहा है, वह स्वप्न पूरा होगा।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the Minister has stated that complete coverage will not be possible in the Tenth Five Year Plan due to paucity of resources. If that is the case, will the Government consider all owing private sector investment in installing FM stations or AM stations or even for digital broadcasting? You are now permitting digital broadcasting for advertisement purposes. Will you permit private investment in hardware, for installing FM stations?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को यह बताना चाहूंगी कि आलरेडी सन 2000 में हमने प्राइवेट प्लेयर्स को FM में आने की इजाजत दे दी है। सन् 2000 से पहले केवल आल इंडिया रेडियो FM लगता था और कोई निजी भागीदारी की अनुमति नहीं थी लेकिन सन् 2000 से, जब से प्राइवेट प्लेयर्स हम लाए हैं, इस समय 25 स्टेशंस ऐसे हैं जो

प्राइवेट प्लेयर्स के हैं, जिनमें से 10 स्टेशंस चालू हो गए हैं और 15 स्टेशंस चालू हो जाएंगे कुछ 29 दिसंबर तक और कुछ 29 अगस्त तक चालू हो जाएंगे और इनकी फर्स्ट ईयर की लाइसेंस फीस भी हमको मिल चुकी है।

सभापति महोदय, FM का दूसरा चरण भी हम घोषित करने वाले हैं जिसमें FM के प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। इसलिए यह जो चिंता है कि हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना में FM का पूरा कवरेज नहीं रखा, यह उचित नहीं है क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद इसमें काफी गति आएगी।

**श्री संजय निरूपम:** सभापति जी मंत्री महोदया ने बताया कि सन् 2000 से प्राइवेट प्लेयर्स आए। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदया अपने जवाब को थोड़ा सुधार लें क्योंकि सन् 2000 से पहले भी प्राइवेट प्लेयर्स थे, मुंबई में Times FM एक जमाने से है सन् 2000 से टेंडरिंग सिस्टम ओपन हुआ। पहले यह था कि जो भी आता था, उससे लाइसेंस फीस लेकर हम उसको एलाऊ कर देते थे। जब टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया गया उसके बाद 25 प्राइवेट प्लेयर्स आए जिनमें से 10 अभी आपरेट कर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** आप अपनी जानकारी मत दो, इनसे जानकारी लो।

**श्री संजय निरूपम:** सभापति जी, आपके जवाब का मैं कायल हूं, इसके बाद कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सन् 2000 से पहले भी प्राइवेट प्लेयर्स थे। सन् 2000 में मैंने ही सदन में स्पैशल मैंशन में यह विषय रखा था कि FM चैनल के लिए टेंडरिंग प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद जब टेंडर ओपन किया गया, उसमें 25 कंपनियां फाईनल हुई और उनमें से 10 कंपनियां आज आपरेट कर रही हैं लेकिन जो 15 कंपनियां आपरेट नहीं कर रही हैं, उनका कहना यह है कि मार्केट कंडीशंस अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने बहुत बड़े दाम देकर ले तो लिया लेकिन वे चला नहीं पर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मार्केट कंडीशंस को फिर से रिव्यू किया जा रहा है दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको कोई डैडलाइन दी गई है कि इतने समय के अंदर आपको प्रसारण शुरू करना पड़ेगा वरना आपको जो लाइसेंस दिया गया है, वह कैंसिल किया जाएगा और फिर से टैंडर फ्लोट किया जाएगा।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति जी, उन्होंने जो जानकारी दी और उसके बाद आपने मुझे कहा कि मैं जानकारी दूं, मैं निश्चित तौर पर उन्हें जानकारी देना चाहूंगी। जहां तक पालिसी के तौर पर प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात है, वह सन् 2000 में तय हुआ। जहां तक बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात है प्राइवेट प्लेयर्स में से कुछ लोग कोर्ट चले गए। जो लोग कोर्ट चले गये, उन्होंने हमारे साथ ऐग्रीमेंट भी साइन नहीं किया जिन लोगों ने हमारे साथ ऐग्रीमेंट साइन किया ऐसे लोगों में से पांच का मुम्बई के अंदर इंटैरिम अरेंजमेंट कर दिया गया और उन लोगों को इंटैरिम की परमिशन

दे दी गयी जिसके कारण पांच चालू हो गये हैं। बाकी जो 9 तीन मैट्रोज में यानी दिल्ली, कोलकोता और चेन्नई में जो स्टेशंस हैं, वह 29 अगस्त तक चालू हो जाएंगे। उन्होंने बेसिन को पैसा दे दिया, हम लोगों को लाइसेंस फी दे दी है। जो नान मैट्रोज हैं, उनमें से भी पांच चालू हो गये हैं और 6 ने फर्स्ट ईयर की लाइसेंस फीस दे दी है। वह 29 दिसम्बर तक वैलिड है और 29 दिसम्बर को वह दूसरी भी दे देंगे। डैडलाइन आलरेडी दी जा चुकी है, नान मैट्रोज को 29 दिसम्बर तक की और मेट्रो वालों को 29 अगस्त, 2003 तक की। इस डैडलाइन के साथ वह ऐग्रीमेंट्स चल रहे हैं और यह 25 स्टेशंस इस डैडलाइन के साथ आपरेशनलाइज हो जाएंगे, यह जानकारी मैं आपको देना चाहती हूं।

**श्री हरीश रावत:** सभापति महोदय आल इंडिया रेडियो की जो कवरेज है, वह राष्ट्रीय कवरेज की तुलना में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनमें बहुत कम है। आपने अपने उत्तर में कहा है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में आप आल इंडिया रेडियो की कवरेज के क्षेत्र को बढ़ाने जा रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या आप जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनमें आल इंडिया रेडियो की कवरेज बढ़े उसके लिए कोई विशेष कदम उठा रही हैं उसमें विशेष तौर पर मैं उत्तरांचल का जिक्र करना चाहूंगा जो आपका अपना राज्य भी है, जहां का आप प्रतिनिधित्व करती हैं। वहां कुछ लो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, क्या उनको अपग्रेड करने की वर्तमान पंचवर्षीय योजना में कोई योजना है, कोई प्रस्ताव है?

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** सभापति महोदय, पहले तो मैं यह बता दूं कि इस सवाल के जवाब में केवल एफ.एम. की कवरेज के लिए हमने कहा। ऑल इंडिया रेडियो केवल एफ.एम. की कवरेज नहीं करता, मीडियम वेव से और शॉर्ट वेव से भी कवर करता है। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव से लगभग पूरा देश कवर्ड है। आज भी अगर रेडियो की प्रासंगिकता कहीं बनती है तो वह दूर-दराज के क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ज्यादा बनती है। टेलीविजन से कहीं ज्यादा वहां रेडियो देखा जाता है। इसीलिए जहां तक कवरेज का सवाल है, जो पंचवर्षीय योजना में मैंने पचास फीसदी कवरेज की बात की है, वह केवल एफ.एम. के कवरेज की बात की है। लेकिन मीडियम वेव और शॉर्ट वेव से इनफार्मेशन और इंटरटेनमेंट सारा जा रहा है। जहां तक उत्तरांचल का सवाल है तो मेरा एक मुंह का पुट भी उस राज्य की तरफ है क्योंकि मैं उत्तरांचल से ही सांसद हूं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जो आपकी चिंता है, वह मेरी चिंता है और उसमें बराबर की साझीदार होते हुए ज्यादा से ज्यादा काम हम उत्तरांचल में रेडियो के लिए करना चाहेंगे।

## Vacancies in High Courts

*372. SHRI K. NATWAR SINGH: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state: